सफलता की कुंजी

अज्ञानी होना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन हमेशा अज्ञानी ही बने रहना गलत होता है

-स्वामी विवेकानंद

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

अनमोल विचार

कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक की उसको किया नहीं जाता

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 18 DECEMBER TO 24 DECEMBER 2019 • VOLUME-18 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

पैसे हाथ में रखते है हाथ जोड़ कर रखते है इसलिए हमारे काम नहीं रुकते है

■ जालंधर से विजय कुमार की विशेष रिपोर्ट

आज कल फगवाड़ा के दो गांव चहेड़ू महेड़ू काफी प्रसिद्ध है जिनका नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। जिसका कारण कई ऐकड़ों में एक गुड़गांव की तर्ज पर बनी बहुमंजिला ईमारतों का बनना परन्तु आज कल यह दोनो गांव हाईकोट में भी काफी चर्चा का विषय बने हुये है जिसका प्रमुख कारण वहां बनी बहु मंजिला इमारतें है। इन बहु मंजिलां ईमारतों के मालिक आज कल डर के साये में जी रहे है। ढाबे को गिराने के लिये अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है परन्तु हकीकत में इसमें गांव फाईवस्टार होटल के मालिक जो कि जालंधर शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति भाई जो किसी समय अकेले मिठाईयों के कारोबारी के रूप में पहचान रखते थे बड़ी चर्चा के विषय बने हुए है।

आज कल उनका लोहा दुनिया के हर कोने में माना जा रहा है उनका धंधा करने का फार्मूला जो किसी ओक्सफर्ड यूनीवर्सिटी या हावर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया नहीं जाता। वैध अवैध जैसा भी काम हो उसको इतनी बाखूबी से अंजाम तक पहुंचाते है उसका एक उदाहरण नहीं अनेकों उदाहरण आपको शहर में देखने को मिल जायेगे जैसे कि ज्योति चौंक से लेकर नकोदर चौंक इनकी करोड़ों रुपए की कीमत की बहुमंजिला ईमारतों को बगैर पार्किंग छोड़े नगर-निगम के अफसरों द्वारा रोड़ के ऊपर सटा के बनवा दिया और ना ही इसकी खबर किसी समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित करने की हिम्मत की गई और ना ही अपने आपको बड़े-बड़े आरटीआई ऐक्टीविस्ट कहलाने वाले शहर के चंद फिकरमंद लोगों द्वारा इसकी आवाज को बुलंद किया गया है और ना ही किसी भी लोअर कोर्ट के जज या हाईकोर्ट के जजों द्वारा कोई कार्यवाही करने की हिम्मत की गई।

लाखों स्क्वायर फीट में वैध और अवैध रूप में अमृतसर दिल्ली हाईवे पर बहुमंजिला ईमारतों की उसारी करवा ली गई।

जहां पर इनकी जमीन के बीच में से सरकारी रास्ते निकलते उसके लिये सरकार द्वारा इनके कद को देखते हुये मास्टर प्लैन लागू होने के बावजूद हर नियम को पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा तार-तार कर दिया और इनको अंडरग्राऊड़ पुल बनाने की मंजूरी देकर अवैध इन्करोचमैंट करवाई गई। नैशनल मीडिया से लेकर लोकल अखबार वाला, केन्द्र से लेकर राज्य के नेता चुनाव लड़ने से पहले इनके यहां हाजरी लगाते और इनमें इतनी ताकत है कि एक पूर्व केन्द्रीय मंत्री का टिकट कटवा कर अपने चहेते को टिकट दिलवा कर केन्द्रीय मंत्री बनवा दिया।

इन्कम टैक्स या सेल टैक्स या पुलिस के किसी अफसर के बेटे या बेटी की शादी हो तो काफी कम दाम में या बगैर पैसे लिए मिठाई देने का मादा रखते हैं। उन बहुमंजिला ईमारतों के मालिकों को इन भाईयों ने दिखा दिया कि पढ़ाई चाहे हमने कम की हो परन्तु हमारी कामयाबी का रहस्य तो यह है कि हम पैसे हाथ में रखते है हाथ जोड़ कर रखते है इसलिये हमारे काम नहीं रुकते है और इसलिए उस इलाके के बादशाह हम थे और हम ही रहेंगे अगर रिक्शा या आटो चालक भी इस इलाके में धंधा करना चाहता है तो हमें रॉयलटी देकर ही करेगा इसलिए इन सभी बहुमंजिला ईमारतों की जांच के लिए सरकार को सीबीआई में केस देकर एक एसआईटी गठित करने का निर्देश देना चाहिए ताकि भ्रष्ट अफसरों की मिली भगत से बनाई गई हर बहुमंजिला ईमारत की विस्तारपूर्वक रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जा सके कि कौन सी ईमारत वैध है और कौन सी अवैध है ताकि आम लोगों में यह संदेश जा सके कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और भेदभाव से उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

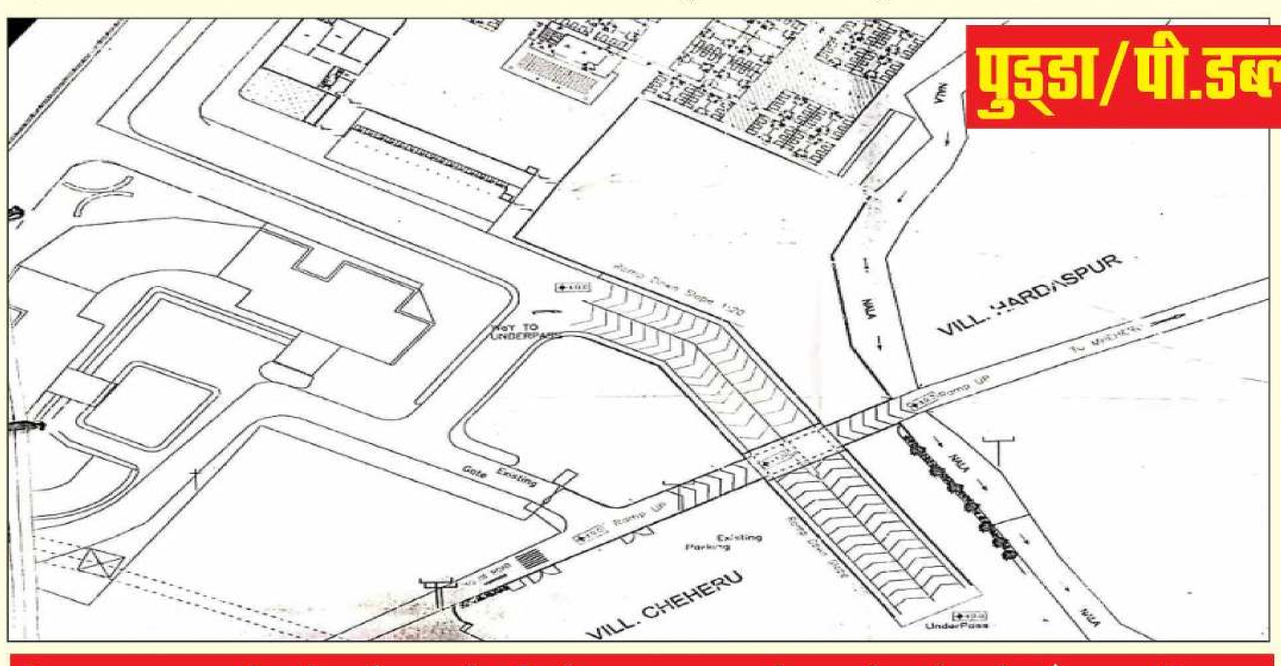

पुड्डा/पी.डब्ल्यू.डी./लोकल बॉडी विभाग

विभाग द्वारा जारी की गई एन.ओ.सी. किस प्रावधान के अधीन दी गई जाँच का विषय।

इसका मूल रूप से प्रमुख कारण एक आरटीआई एक्टीविस्ट द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई जिसमें उसने यहां बनी हुई बहुमंजिला इमारतों को अवैध करार देते हुए इनको ढाहने के लिये हाईकोर्ट में मांग की गई है इसको देख कर तो बॉलीवुड के अदाकार गोविंदा और कादरखान द्वारा फिल्माया गया एक फिल्म का सीन याद आ जाता है जिसमें कादरखान अपने फाईवस्टार होटल के सामने बने गोविंदा के

इन बहुमंजिला इमारतों में से कौन सी वैध और कौन सी अवैध है जाँच का विषय।

रोड़ सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग लोगों की सेफ्टी से ज्यादा अपनी सेफ्टी में मशरूफ

नैशनल हाईवे विभाग

कुछ दिनों पहले शुरू हुए रामामंडी पुल के बदतर हालात का कौन जिम्मेदार?

■ जालंधर से प्रभात सूरी की विशेष रिपोर्ट

पिछले दिनों डिप्टी कमिशनर जालंधर द्वारा एक लिखित आडर ट्रैफिक पुलिस नैशनल हाईवे को एक पत्र जारी कर लिखा गया कि हमारे रोड़ सेफ्टी इंजीनरिंग विभाग द्वारा चिन्हित किए हाई एक्सीडैंट जोंन जिनकी संख्या 20 से 21 दर्शाई गई जिनमें कि मुख्य रूप से फेयर फार्म रिजोर्ट, पुल नीचे वेरका मिल्क प्लांट, बाई प्वाइंट भगत सिंह कालोनी, टी प्वाइंट हिल व्यू कालिया कालोनी, पुलिस स्टेशन-8 अधीन बूटा सिंह बिल्डिंग मैटीरियल स्टोर, पठानकोट चौंक, लम्मा पिंड चौंक, टी प्वाइंट- सुच्ची पिंड चौंक, सामने जेसी रिसोर्ट, पी.ए.पी चौंक, रामामंडी चौंक, बडिंग गेट दकोहा फाटक, मोदी रिसोर्ट, धनोवाली रोड, गड़ा रोड सामने जवाहर नगर, बस स्टैंड, चुन्नमुन्न चौंक, अवतार नगर, ज्योति चौंक, शीतल नगर मकसूदां, टैगौर अस्पताल, टी प्वाइंट जिंदा रोड और रेरू की सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग टीम द्वारा पहचान किया गया परन्तु रोड़ सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रामामंडी पुल के ऊपर डाली गई लुक बजरी को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया गया अगर वाक्य में ही यह विभाग लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया गया तो पुल के ऊपर लैवल जो कि ऊपर नीचे है उसे ठीक करवाए और लोगों को सफर के दौरान लग रहे झटके और पुल

के बीच में बने उबड़ खाबड़ खड्डों से बच कर अपनी जान बचानी पड़ रही है और सेफ्टी इंडीनियरिंग विभाग इसकी जांच करें कि ठेका प्राप्त कंपनी द्वारा इतने गंदे तरीके से इस लुक बजरी के काम को अंजाम क्यों दिया गया और लोगों को सरवाईकल जैसी गंभीर बीमारीयों से पीड़ित करवाया गया और कई टू व्हीलर सवार अनबैल्स होकर नीचे गिर गये जिससे कि उन लोगों को गंभीर चोटों का शिकार होना पड़ा। इन पीड़ित लोगों को हाईवे के भ्रष्ट अफसरों से और ठेका प्राप्त कंपनी से मुआवजा दिलवाये जिलाधीश।

जामिया हिंसा मामले में 10 गिरफ्तार, कोई छात्र शामिल नहीं

नई दिल्ली/न्यूज नेटवर्क

शहर के जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में कोई भी छात्र नहीं है।

विश्वविद्यालय रविवार को उस वक्त जंग के मैदान में तब्दील हो गया था जब पुलिस परिसर में घुस आई थी और वहां बल प्रयोग किया था। दरअसल, संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी

हुई थी जिसमें चार डीटीसी बसों, 100 निजी वाहनों और 10 पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

IELTS • PTE • TOEFL

SPOKEN ENGLISH

TOURIST VISA | STUDY VISA | PR

WORK PERMIT | HOLIDAY PACKAGES

CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE

9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal.

HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com

Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin

उक्ति

जो व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, वे अपने आत्मविश्वास की नौका पर सवार होकर विपत्तियों की सभी नदियों को आराम से पार कर जाते हैं। विपत्तियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पातीं।

■ लेनिन

www.jalandharbreeze.com

साप्ताहिक
18 दिसंबर से 24 दिसंबर 2019
जालंधर ब्रीज

प्रसंग

अपराधियों के लिए सख्त सरकार

प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया। अभियान में प्रदेश भर में 5947 अवैध हथियार एवं कुल तीन लाख छह हजार 856 लीटर अवैध मदिरा जप्त की गई। अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई पहल को नजरंदाज कतई नहीं किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में बीते एक वर्ष में पहली बार पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने क्रांतिकारी प्रयास किए हैं। नई सरकार के इन प्रयासों से पुलिस महकमे में विश्वास का भाव जागा है। परिणामस्वरूप प्रदेश की पुलिस पहले से अधिक मुस्तैद हुई है। अभी कुछ समय पहले तक 24 घंटे सातों दिन की ड्यूटी निभाना पुलिस के हिस्से में था। लगातार ड्यूटी के कारण पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य की समस्या और मानसिक अवसाद के ढेरों मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में नई सरकार ने पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का निर्णय लिया। पुलिसकर्मियों के हित में पहली बार इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया। पुलिस में आरक्षक तथा निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मचारियों को निःशुल्क आवास सुविधा देने के लिए 25 हजार आवास का निर्माण कराया जा रहा है। प्रथम चरण में 5000 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में 5000 आवास का निर्माण तेजी से जारी है और तृतीय चरण में 5000 आवासों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

एसएएफ के आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक, जिनकी सेवा पांच वर्ष की हो गई है, उनका जिला पुलिस में 25 प्रतिशत तक पद पर संविलियन करने के लिए कार्य-योजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलने पर अन्य विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने की योजना प्रचलन में है। पुलिस परिवार की महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए वर्ष 2003 में पुलिस अनुसूचित जाति/जनजाति महिला कल्याण समिति का पंजीयन कराकर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, लाइब्रेरी एवं बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये सेवा केंद्र पिछले कई सालों से निष्क्रिय हो गए थे। अब इन्हें सक्रिय कर इनमें पुलिसकर्मियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग के ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसके साथ पुलिस की अन्य इकाइयों की आश्रित महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विसबल रेंज ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में केंद्रीय कल्याण निधि से राशि स्वीकृत की गई है। सेनानी 6वीं वाहिनी जबलपुर, 2री वाहिनी ग्वालियर, प्रथम वाहिनी इंदौर, 15वीं वाहिनी इंदौर, 24वी वाहिनी जावरा और 32वीं वाहिनी उज्जैन में कल्याण केंद्र स्थापित कर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ब्यूटीशियन, सिलाई, मेकअप आर्टिस्ट एवं ब्यूटी थेरेपिस्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे आश्रित महिलाएं एवं बच्चियों को सरलता से रोजगार मिल सकेगा तथा वे आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर हो सकेंगी। प्रदेश पुलिस की सभी इकाइयों में आंगनवाड़ी, शिशु गृह तथा झूलाघर शुरू करवाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार के अपराधों के खिलाफ सख्त रवैये से अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। नई सरकार के प्रति विश्वास का भाव आम आदमी में बढ़ा है। खासतौर पर महिला सुरक्षा को लेकर नई सरकार की कार्रवाई से अपराधियों में भय का वातावरण बन गया है। इस वर्ष प्रथम पांच माह में महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों में न्यायालयों से 1400 से अधिक प्रकरणों में सजा दिलाई गई है। यह गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में नौ प्रतिशत अधिक है। 27 मामलों में अपराधियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया गया। अभियान में प्रदेश भर में 5947 अवैध हथियार एवं कुल तीन लाख छह हजार 856 लीटर अवैध मदिरा जप्त की गई। अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। माह जनवरी से अप्रैल तक की अवधि में नारकोटिक्स विंग ने 17 हजार किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ तथा करीब 56 हजार अफीम और गांजे के पौधे जब्त किए। प्रतिबंधित नशीले केमिकल्स की 32 हजार से ज्यादा सीरप व गोलियां जब्त की गईं। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 1285 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट में भी कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के 30 हजार 895 प्रकरणों में 32 हजार 919 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कुल 30 हजार गिरफ्तारी वारंट की तामीली कराई गई। तामीली का प्रतिशत लगभग 69 रहा। गुमशुदा बालक-बालिकाओं को खोजने के लिए 15 मार्च से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर कुल 1054 बच्चों को ढूंढने में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली।

नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस ने 14-14 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों अशोक उर्फ मंगेश और नक्सली महिला नंदे को जिला बालाघाट के थाना लॉजी के अंतर्गत ग्राम नेवरवाही में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा इस अभियान में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देने वाले 19 कर्मियों को क्रम पूर्व पदोन्नति (आउट ऑफ टर्न) दी गई है। गुंडा विरोधी अभियान में पुलिस अधीक्षक, उज्जैन के नेतृत्व में कुख्यात बदमाश रोनक एवं उसके साथियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। मध्यप्रदेश के सभी पुलिस महानिरीक्षकों को उनके अधीनस्थ जिलों में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं में भी पुलिस को विधिक प्रक्रिया एवं जांच के आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए 17 से 45 वर्ष आयु वर्ग की बीपीएल वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क स्मार्ट फोन दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें आत्म-रक्षा के लिए एप इंस्टाल होगा। महिला द्वारा इसके उपयोग से पुलिस तत्काल मदद के लिए पहुंच सकेगी। इस एप से शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी महिलाओं को प्राप्त हो सकेगी।

प्रदेश में जुलिया रिबेरा, मालिमाथ, सोली सोराबाजी कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर पुलिस मॉडल एक्ट लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग अथवा भीड़ द्वारा अन्य कारणों से दुष्प्रेरित होकर की जाने वाली घटनाओं के खिलाफ कानून बनाने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में आतंकवाद विरोधी कानून की तर्ज पर सांप्रदायिक/जातिगत फसादत के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। नई सरकार द्वारा अपराधों पर नियंत्रण पाने तथा अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए कठोर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जा रहा है। सरकार के संवेदनशील व्यवहार से पुलिस प्रशासन में चुस्ती आ गई है। आम आदमी में भी सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। प्रदेश में शांतिपूर्ण वातावरण तैयार हो गया है। कुल मिलाकर कमलनाथ प्रदेश में सुशासन लाने का जो संकल्प धारण किए है, उसके असर दिखने लगे हैं। प्रदेश में शांति स्थापित है और व्यवस्था को आम आदमी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। एक वर्ष के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने साबित कर दिखाया है कि बेहतर सुशासन की स्थापना कैसे की जाती है।

■ दुर्गेश रायकवार
(सहायक संचालक , जनसंपर्क)

विचार

हिंसा पर कोर्ट का रुख सही

नागरिकता संशोधन कानून पर देशभर में जारी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख दिखाया है, वह अभी के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। हमारी ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि कुछ हुआ नहीं कि हिंसा करने लगो। यह प्रवृत्ति सही नहीं है, इस पर रोक लगानी होगी।

नागरिकता संशोधन कानून पर देशभर में जारी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख दिखाया है, वह अभी के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के हिंसक प्रदर्शन पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले की कल सुनवाई करेगी लेकिन उससे पहले हिंसा रुकनी चाहिए। जयसिंह ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे के सामने दलील रखी कि पूरे देश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं और अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से देखें तो यह टिप्पणी सिर्फ इसी मामले को लेकर नहीं है। देश में एक धारणा बन चुकी है कि कुछ हुआ नहीं कि हिंसा का सहारा ले लिया जाता है। राम-रहीम की सजा हो या फिर गोहत्या को लेकर मारपीट। हर जगह हिंसा का वर्चस्व दिखा है।

सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ अपनी बात कहने का दूसरा माध्यम भी हो सकता है। विरोध का मतलब हर समय हिंसा नहीं होता है। सरकारी संपत्तियों को जलाना नहीं होता है। मगर नागरिक संशोधन कानून में पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल और दिल्ली में हर जगह हिंसा का रूप देखने को मिला। जब पूरा देश हिंसा की आग में झुलस रहा था, तभी दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल का विरोध उन लोगों के लिए नजीर बन रहा था, जिनका मकसद हिंसा फैलाना था। रेप के मामलों के खिलाफ मालीवाल 13 दिनों तक आमरण अनशन पर रहीं। मालीवाल के विरोध जताने के तरीके पर भी चला जा सकता है। कानून के विरोध में पूर्वोत्तर से लेकर दिल्ली तक की जो तसीर देखने को मिली, वह सही नहीं है। ट्रेनें जलाई गईं, दर्जनों बसों को आग के हवाले किया गया। कुछ चंद लोगों ने पूरे राज्य का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। स्कूल-कॉलेज बंद करने पड़े। छुट्टियां मनाने गए पर्यटकों की जान पर बन आई। दूसरे देशों को भारत में अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ी।

ऐसे और भी उदाहरण हैं, जो भारत की बहुरंगी तस्वीर को मैला करते हैं। मगर इससे किसी को मतलब नहीं। हर कोई कानून के विरोध में ऐसे सड़क पर उतर आया, जैसे उसका नंबर देश से बाहर जाने वालों में सबसे पहला है। सरकार यह बार-बार कह चुकी है कि किसी भी नागरिक को देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा, यह कानून सिर्फ भारत में शरण लेने वालों के लिए है, तो इस पर भरोसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए। भारत में अवैध तरीके से घुसे नागरिकों को अगर बाहर किया भी जाएगा तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जामिया के छात्रों को इसमें क्या दिक्कत। आज जामिया के जिन छात्रों की वजह से पूरे संस्थान को बदनामी का दाग झेलना पड़ा, उसके लिए क्या किया जाएगा, यह अभी तय करने की जरूरत है। पढ़ने वाले जो छात्र जबरदस्ती घर भेजे गए हैं, उनका क्या कसूर है।

उच्च शिक्षा का स्वर्णिम वर्ष

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही उल्लेखनीय कदम उठाकर करोड़ों युवाओं के मन में सुनहरे कल का विश्वास जगाया है। मध्यप्रदेश के करोड़ों लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं का यह वर्ष उमंग और विश्वास का प्रतीक बन गया है। अच्छी और बेहतर शिक्षा से प्रदेश के युवाओं का भविष्य बेहतर बने, इस लक्ष्य को लेकर सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता से युवाओं का एक स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित होता है। इसीलिए मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ही उल्लेखनीय कदम उठाकर करोड़ों युवाओं के मन में उनके सुनहरे कल का विश्वास जगाया है। देश के चुनिंदा और बेहतर शिक्षा के लिए अग्रणी प्रदेशों के समकक्ष बनने की और मप्र ने शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर करने के साथ मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। वहीं आधुनिक संसाधनों से शिक्षा संस्थानों को परिपूर्ण करना, अधोसंरचना का निर्माण, बेटियों के लिए सुलभ और बेहतर शिक्षा, प्रवेश प्रक्रिया का सरलीकरण, कौशल विकास और रोजगारमुखी शिक्षा, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारियों की नियुक्ति, ई-लाइब्रेरी और खेल मैदान की उपलब्धता जैसी नीतियों के लागू और पूरा होने से प्रदेश का शैक्षणिक परिवेश रचनात्मक और विश्वसनीय बना है।

मध्यप्रदेश ने उच्च शिक्षा की अनदेखी का बुरा दौर देखा है, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी कई सालों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे, इसका असर प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर भी पड़ा। लेकिन वर्तमान सरकार युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए संकल्पित है। कमलनाथ सरकार ने प्रतिबद्धता से इस और कदम उठाए हैं और इसीलिए प्रदेश के शिक्षा संस्थान अब प्राध्यापक विहीन नहीं रहेंगे। उच्च स्तर की परीक्षाओं में चयनित हमारे काबिल शिक्षक प्रदेश के कोने कोने में उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए विद्यार्थियों के बीच उपलब्ध होंगे। साथ ही आधुनिकतम लाइब्रेरी में उच्च स्तर और गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें हों और उसका लाभ आम विद्यार्थी को मिले इसलिए ग्रंथपालों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा के साथ युवा खेल की विधाओं में भी राज्य और देश का नाम रोशन करें इसलिए कोई भी महाविद्यालय अब क्रीड़ा अधिकारी विहीन नहीं होगा, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य विद्यार्थी के शैक्षणिक विकास के साथ उसका सर्वांगीण विकास भी है। प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाते हुए इसे विद्यार्थी के लिए सुलभ बनाया गया है। महाविद्यालयों की अपनी जमीन हो और आधुनिक संसाधनों के साथ उनका अपना खेल मैदान, गार्डन इत्यादि भी हो। कमलनाथ सरकार ने शासकीय महाविद्यालयों की भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे इस साल तक पूर्ण करने की योजना है। इसमें 30 वर्षों की विकास योजना को आधार बनाकर विकास किया जा रहा है। शिक्षा संस्थानों की अधोसंरचना विकास के कार्य लगातार किए जा रहे है। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए वर्चुअल कक्षा का प्रसारण लगातार किया जा रहा है, इससे प्रदेश के कोने कोने तक शिक्षा के बेहतरीन वातावरण को बनाने में मदद मिल रही है। उच्च शिक्षा विभाग में पिछले कई वर्षों से कर्मचारी, अधिकारियों की लंबित शिकायतों का अंबार लग चुका है। अफसोस है कि पिछले कुछ वर्षों से इन समस्याओं की अनदेखी की गई। कर्मचारी और अधिकारियों की लंबित मांगों के अविलंब निवारण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण कमेटी कृत-संकल्पित होकर काम कर रही है। प्राध्यापकों के ज्ञान और अनुसंधान का लाभ सभी को मिले और उनकी काबिलियत शासन के उच्च स्तर तक पहुंचे, अब राजीव गांधी ज्ञान ज्योति अभियान के द्वारा यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु नॉलेज कोर्पोरेशन से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ रोजगार मिलने की संभावनाएं सुनिश्चित होगी। विद्यार्थियों को उद्यमिता कौशल तथा व्यक्तित्व विकास, अंग्रेजी भाषा कौशल, डिजिटल लिट्रेसी और कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना से औद्योगिक नवाचार की नई संभावनाएं जागेगी। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में औद्योगिक नवाचार के तहत स्थानीय संसाधनों एवं स्थानीय बड़े, छोटे एवं मझोले उद्योगों की जरूरत के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार करने व पीपीपी मॉडल पर उद्योगों के द्वारा प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और कौशल विकास की और युवा अग्रसर भी होंगे।

कमलनाथ सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कई नवाचार के कार्य कर रही है जिसके अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया को नियमित और समयावधि में पूर्ण करने के लिए सुधार के साथ एमपी ऑनलाइन को बेहतर बनाया गया है जिससे समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हुई है। बालिकाओं के लिए प्रवेश शुल्क पूरी तरह माफ करने से लाखों बेटियां लाभान्वित हुई हैं। बेटियों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शुमार है। कन्या महाविद्यालयों में पुलिस चौकी की स्थापना कर उन्हें बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल दिया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा कौशल एवं विकास गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के लिए भी शिक्षित किया जा सके। हम शिक्षा का ढांचा कुछ इस प्रकार संचालित करने जा रहे है जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो और वह उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें अर्थात उसका आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक और भौतिक उन्नति एक साथ हो।

मध्यप्रदेश के करोड़ों लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं का यह वर्ष उमंग और विश्वास का प्रतीक बन गया है। अच्छी और बेहतर शिक्षा से प्रदेश के युवाओं का भविष्य बेहतर बने, इस लक्ष्य को लेकर कमलनाथ सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसके उजले परिणाम सामने आ रहे है। बहरहाल बेहतर शिक्षा से स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण की शानदार शुरुआत हो चुकी है। उत्कृष्ट शिक्षाविदों को जोड़कर उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्कृष्ट संस्थानों की तर्ज पर ऑटोनामी के साथ उत्कृष्ट संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए तीन हजार करोड़ रुपए मूल्य की वर्ल्ड बैंक परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना में हम 200 महाविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहे हैं, 46 कन्या महाविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण, राज्य में नवीन आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना के साथ राजगढ़ में एक नवीन व्यावसायिक महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। 33 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत करने के साथ विश्व बैंक परियोजना के तहत 153 कम्प्यूटर लैब, 2000 स्मार्ट क्लासेस, 200 लैंग्वेज लैब,200 ई-लाईब्रेरी तथा विज्ञान विषयों की प्रयोगशालाएं निर्मित किए जाने की योजना है। रोजगार वृद्धि के लिए एक कॉमन कॅरियर पोर्टल विकसित किया जा रहा है जिससे छात्रों एवं उद्यमियों को एक प्लेटफार्म मिलेगा। हमारी सरकार प्रदेश की खुशहाली और लोक कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है।

■ जीतू पटवारी
(मंत्री, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश)

ट्विटर

सरकार जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उसे यह लगता है कि वह बलपूर्वक कुछ भी करती रहे और देश की जनता चुपचाप उसे देखती रहेगी।

अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस नेता

केंद्र सरकार सभी को अपनी बात रखने का मौका देती है, पर हिंसा के जरिए अपनी बात करने या मांग मनवाने को मंजूर नहीं किया जाएगा। शांति से बात होनी चाहिए।

संबित पात्रा, भाजपा प्रवक्ता

सत्यार्थ

सिकंदर और फकीर

जब सिकंदर भारत आया, तो एक फकीर से उसकी मुलाकात हुई। सिकंदर को देखते ही फकीर हंसने लगा। फकीर को हंसते देख सिकंदर ने सोचा कि यह तो मेरा अपमान है। उसने आंखें तरेरते हुए फकीर की ओर देखा। फकीर इस बार भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। सिकंदर गुस्से से तमतमा उठा, पर वह खुद पर नियंत्रण किए हुए था, क्योंकि सामने एक फकीर था। फिर भी इतना तो उसने कह ही दिया कि शायद तुम जानते नहीं, मैं सिकंदर महान हूं। इस पर फकीर और भी ज्यादा जोर से हंसने लगा। उसने कहा- मुझे तो तुम में कोई महानता नजर नहीं आती। मैं तो तुम्हें बड़ा दीन व दरिद्र देखता हूं। सिकंदर बोला-तुम पागल हो गए हो। मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है। ऐसा कोई नहीं, जो मेरे आगे अदब से नहीं झुकता हो। तब उस फकीर ने कहा- ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम अभी साधारण ही हो। फिर भी तुम कहते हो, तो मैं मान लेता हूं। मगर कहो तो तुमसे एक बात पूछ लूं। सिकंदर थोड़ा शांत हुआ और बोला-पूछो। फकीर ने कहा-मान लो कि तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और आसपास दूर-दूर तक तुम्हारे पास पानी का कोई साधन नहीं है। अगर उस समय पानी मिल जाए, तो एक गिलास पानी के बदले क्या दोगे। सिकंदर बोला- मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। फकीर ने कहा- यदि वह आधे राज्य के लिए न माने तो? सिकंदर ने कहा- तो मैं उसे अपना पूरा राज्य दे दूंगा। फकीर फिर हंसने लगा और बोला- तुम्हारे राज्य का मूल्य है 'बस एक गिलास पानी' और तुम व्यर्थ में ही घमंड से चूर हो रहे हो। यह सुनते ही सिकंदर पानी-पानी हो गया और समझ गया कि व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए।

■ जनार्दन शर्मा

वह शख्स हैं आबिद सुरती। लेखक, नाटककार, पटकथाकार, कार्टूनिस्ट, चित्रकार, पत्रकार और पर्यावरणविद आबिद सुरती। वह 80 साल की उम्र तक 80 किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने भारत को पहला सुपर हीरो बहादुर दिया और लाखों-करोड़ों लोगों की होठों पर मुस्कान लाने वाला किरदार ढब्बू जी भी रचा।

84 साल का नौजवान पानी बचाने में लगा रहा जी-जान

हर रविवार की सुबह 84 साल के एक नौजवान मुंबई के उपनगर मीरा रोड की सड़कों पर निकलते हैं। जब लोग छुट्टी के आलस में होते हैं, तब वह किसी सोसायटी में घुसकर हर फ्लैट की घंटी बजाते हैं। उनके साथ एक प्लंबर और एक वॉलंटियर होता है। वह हर फ्लैट के नल चेक करके उनकी मरम्मत कराते हैं। इस तरह बूंद-बूंद टपकता पानी बचाकर उन्होंने पिछले 12 साल में करीब 3 करोड़ लीटर पानी को बर्बाद होने से बचाया है। वह शख्स हैं आबिद सुरती। लेखक, नाटककार, पटकथाकार, कार्टूनिस्ट, चित्रकार, पत्रकार और पर्यावरणविद आबिद सुरती। वह 80 साल की उम्र तक 80 किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने भारत को पहला सुपर हीरो बहादुर दिया और लाखों-करोड़ों लोगों की होठों पर मुस्कान लाने वाला किरदार ढब्बूजी भी रचा।

12 साल पहले शुरू हुआ अभियान

12 साल पहले की बात है। आबिद अपने दोस्त के घर गए, तो वहां एक नल से पानी टपकता देखा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक महीने में एक हजार लीट पानी इसी टप-टप में बह जाता होगा। बस उसी दिन ठान लिया कि यह टप-टप रोकनी है। आबिद कहते हैं कि मैं बेहद मामूली जगह पर रहा हूं। वहां मैंने जरा से पानी पर लोगों को किट-किट करते देखा है। इसलिए मैं पानी बचाने में जुट गया। उनका कहना है कि मैं गंगा को तो नहीं बचा सकता, लेकिन पानी की बर्बादी तो रोक ही सकता हूं।

मुफ्त में करते हैं नल ठीक

आबिद ने मुहिम शुरू करने के लिए एक बूढ़े प्लंबर से पूछा था, मैं हर रविवार को तीन घंटे तक लोगों के घर जाकर उनके नल मुफ्त में दुरुस्त कराऊंगा। आप इस काम के कितने पैसे लोगे? प्लंबर सिर खुजाते हुए बोला था, जब आप किसी से इस काम के पैसे नहीं लोगे, तो मैं आपसे कैसे लूंगा? आबिद ने इस काम के लिए वन मैन एनजीओ ड्रॉप डेड फाउंडेशन बनाया। उन्हें उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान का एक लाख रुपए और महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का 50 हजार रुपए का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला, तो पानी बचाने की मुहिम के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। वह रकम खत्म हुई, तो अमिताभ बच्चन ने अपने शो आज की रात है जिंदगी, में बुलाकर उन्हें 11 लाख रुपए का चेक दिया। इस तरह काम रुकने की कभी नौबत नहीं आई। आबिद बताते हैं कि बहुत से लोग मेरे एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि यह तो वन मैन एनजीओ है, आप भी इसी तरह काम शुरू कर दो। जगह-जगह बहुत से लोग ऐसा करने भी लगे हैं। आबिद की मुहिम की गूंज दुनिया भर में है। आबिद के काम की डॉक्यूमेंट्री फिल्में यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में दिखाई गई, तो वहां से उनके पास बधाई के फोन आने लगे।

हर सफलता की कुंजी कठिन परिश्रम, धैर्य और समर्पण है

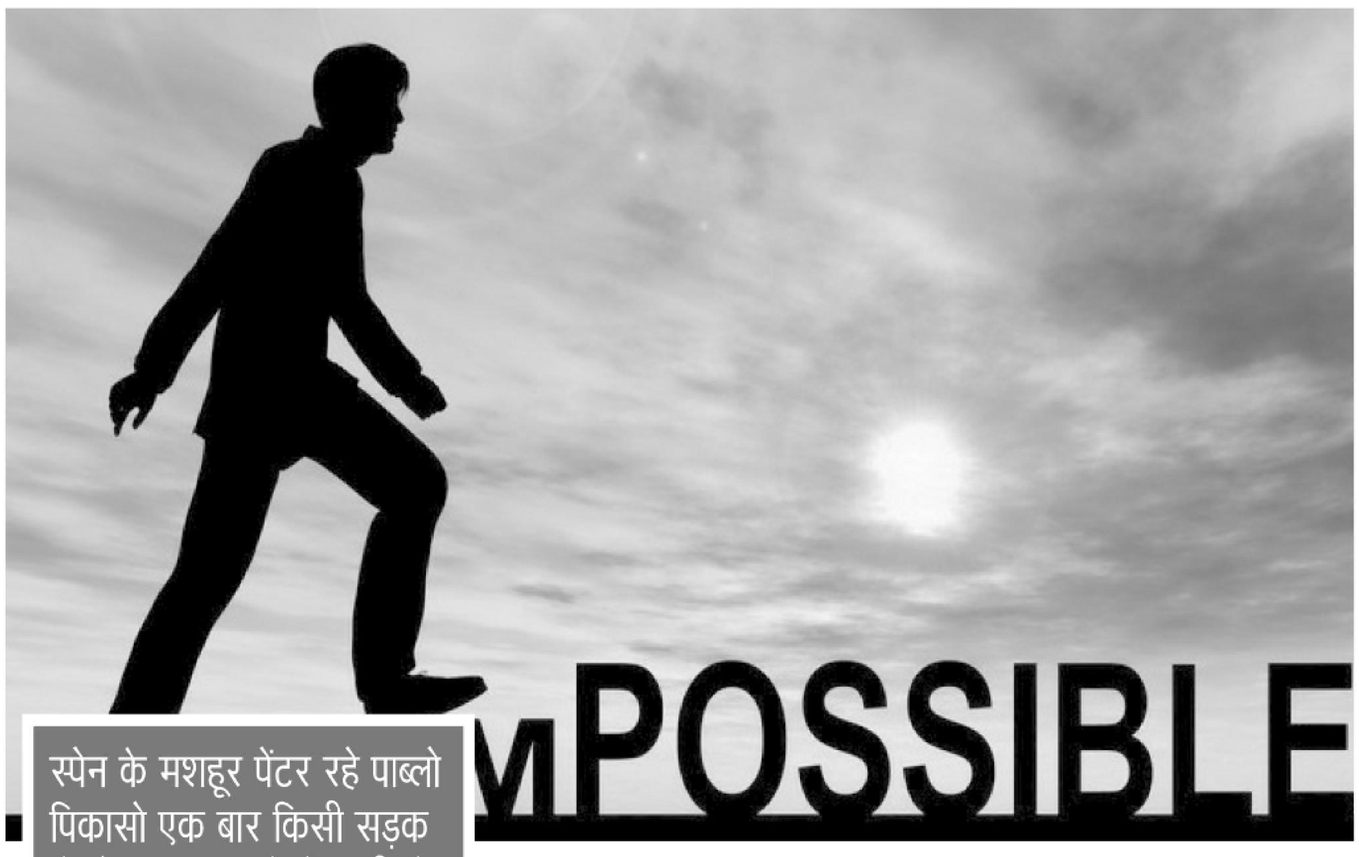

स्पेन के मशहूर पेंटर रहे पाब्लो पिकासो एक बार किसी सड़क से होकर गुजर रहे थे। वहीं से एक महिला भी गुजर रही थी। महिला ने पिकासो को देखा। वह उन्हें पहचान गई और दौड़कर उनके पास गई। महिला ने पिकासो से कहा- 'मैं आपकी बड़ी प्रशंसक हूं। आपकी पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बना सकते हैं? महिला की बात सुनकर पिकासो मुस्कुराए और निवेदन करते हुए बोले- 'मेरे पास पेंटिंग बनाने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त मेरे हाथ खाली हैं। मैं किसी और दिन आपके लिए पेंटिंग बना दूंगा।'

महिला बोली- 'पता नहीं। किसी और दिन में आपको मिल पाऊंगी या नहीं। इसलिए आप आज ही मेरे लिए पेंटिंग बना दीजिए। महिला के बार-बार आग्रह करने पर पिकासो ने एक कागज का छोटा सा टुकड़ा लिया और अपनी शर्ट की जेब से पेन निकालकर कागज के टुकड़े पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। दस सेकंड के बाद पिकासो ने कागज पर ड्रॉइंग पूरी कर दी और महिला को देते हुए कहा- 'यह लीजिए यह पेंटिंग लाखों डॉलर की है।' महिला को अचंभा हुआ कि पिकासो ने कैसे दस सेकंड में पेंटिंग पूरी कर दी और उसकी कीमत लाखों डॉलर बता रहे हैं। उस वक्त महिला ने पिकासो को धन्यवाद दिया और पेंटिंग लेकर चली गई। घर जाकर वह सोचने लगी कि पेंटिंग की कीमत के बारे में शायद पिकासो मजाक कर रहे होंगे। पेंटिंग की सही कीमत जानने के लिए वह बाजार गई और देखकर दंग रह गई कि पेंटिंग की कीमत वाकई लाखों डॉलर है। संयोग से एक बार फिर अचानक महिला की मुलाकात पिकासो से हुई। काफी उत्साहित होकर वह पिकासो से मिली और कहने लगी- सर आप एकदम सही थे। आपने जो पेंटिंग बनाई थी वह लाखों डॉलर की है। आगे अपनी बात जारी रखते हुए महिला ने कहा कि 'मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूं। मैं भी सीखना चाहती हूं कि इतने कम समय में कैसे लाखों डॉलर की पेंटिंग बनती है।

पिकासो ने मुस्कुराते हुए महिला से कहा- मैंने जो पेंटिंग दस सेकंड में बनाई है, उसकी कीमत लाखों डॉलर है। लेकिन, यह मेरे जीवन के तीस सालों की कीमत है। जिसे कला सीखने के लिए मैंने कठिन परिश्रम, संघर्ष, समर्पण से सींचा है। अगर तुम भी यह करना चाहती हो, तो अपने जीवन में इन चीजों को शामिल करो। तुम भी एक दिन ऐसी ही पेंटिंग बना सकोगी। पिकासो की बात सुनकर महिला अवाक रह गई।

सीख

1. कठिन परिश्रम, संघर्ष, समर्पण से आप बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं।
2. जीवन में कुछ भी बड़ा करने के लिए कठिन परिश्रम, संघर्ष और पूरे समर्पण की जरूरत होती है।
3. इंसान में लगन हो तो वो जीवन में कुछ भी पा सकता है।

किसानों के लिए फरिश्ते बने सौंदाना के मोहन भालेकर

खेती शब्द सुनकर दिमाग में तीन चार तस्वीरें एकसाथ घूमने लगेंगी। इसमें खेत, किसान और हल सबसे पहले आएंगे। हल की जगह अब ट्रैक्टर ने भले ले ली हो, लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में फिलहाल हल भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि इन्हें ठीक करनेवाले काफी कम लोग बचे हैं। वहां के सौंदाना गांव में तो सिर्फ एक शख्स ही इन पुराने औजारों को ठीक कर सकता है। इनका नाम है मोहन भालेकर। मोहन के पिताजी भी यही काम किया करते थे। वहां इस हल को पर नी यंत्र बोला जाता है। भालेकर पेशे से कारपेंटर हैं और सौंदाना में वह फिलहाल किसानो के हल या उस जैसे पुराने औजार ठीक करते हैं। हालांकि, भालेकर के लिए यह अब फायदे का सौदा नहीं है। कई बार उन्हें फ्री में भी काम करना पड़ता है। 10 साल पहले हर एक किसान उन्हें सर्विस के बदले 25 बोरे ज्वार (हर साल) देते थे। तब भालेकर के पास ऐसे कुल 40 किसान थे। लेकिन अब सर्विस लेनेवाले लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई है। ऐसा ट्रैक्टर आने और लोगों के खेती छोड़ने की वजह से हुआ है। अब हर साल भालेकर को सिर्फ 5 बोरे मुश्किल से मिलते हैं। मराठवाड़ में पिछले पांच सालों में तीन बार सूखा पड़ चुका है। इस साल भी जहां राज्य की बाकी जगहों पर जरूरत से ज्यादा बारिश हुई, मराठवाड़ा में सिर्फ 73 प्रतिशत बारिश हुई। जो बहुत सामान्य स्तर है।

औजार ठीक नहीं होंगे तो किसान क्या करेंगे?

बारिश में देरी की वजह से फसल खराब होने के बाद भालेकर बिना किसी पेमेंट के काम करते हैं। इसपर वह कहते हैं कि अगर मैं उनके औजार ठीक नहीं करूंगा तो कौन करेगा? किसान कुछ भी बो या उगा नहीं पाएंगे। अपने पेमेंट के सवाल पर भालेकर कहते हैं कि सब अच्छा होने पर वे मुझे पेमेंट कर देंगे। भालेकर से पर नी यंत्र ठीक करवाने वाले एक किसान बताते हैं कि एक ट्रैक्टर का प्रतिदिन का किराया 1200 रुपए है। मुझपर इतना पैसा नहीं है। मेरे पास तो भालेकर को देने के लिए भी पैसा नहीं है। भालेकर ने 15 साल की उम्र में अपने पिता से यह काम सीखा था। उस वक्त उनके पिताजी उन्हें आगे पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। हालांकि, अब भालेकर अपने बच्चों को किसी तरह पढ़ा रहे हैं। उनके दो लड़के कॉलेज में हैं। भालेकर के पिता जिनकी उम्र अब 80 साल के करीब हो चली है, वह अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वह बताते हैं कि एक वक्त पर उनके पास कई सारे ऑर्डर्स आते थे।

छोड़ी विदेश की नौकरी, बच्चों को पढ़ाने लौटे अपने देश

विदेश में नौकरी, अच्छा पैकेज, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बेहतर मुकाम के बावजूद कुछ ऐसा था जो मन को कचोट रहा था। तमाम सुविधाओं का मोह छोड़कर वतन लौटकर नई पीढ़ी को शिक्षित करने का फैसला लेना आसान नहीं था। परिचितों ने मजाक के साथ ही डराया भी। लेकिन अनूप ने मां का सपना पूरा करने की ठान ली थी। नतीजा आज सामने हैं। कुछ समय पहले तक कटाक्ष करने वाले आज सराहना करते हैं, यह कहते हुए अनूप के चेहरे पर एक अलग सा सुकून नजर आता है। गोमतीनगर के विजय खंड निवासी अनूप गुप्ता पिछले 9 वर्षों से शहर के प्राइमरी स्कूलों

रैथा प्राथमिक विद्यालय से आगाज

अनूप बताते हैं कि, मां हमेशा कहती थीं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज के हर इंसान की जिम्मेदारी है। ऐसे में वर्ष 2011 में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। आगाज बक्शी का तालाब के रैंथा प्राथमिक विद्यालय से हुआ। शुरू में बच्चों और अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताते हुए स्कूल भेजने के लिए जागरूक करते थे। इसके बाद 2013 में आई केयर इंडिया संस्था बनाई। फिर शहर और आसपास के प्राइमरी स्कूलों में जाकर बच्चों को एक्टिविटी बेस लर्निंग, व्यवहारिक बदलावों, हेल्थ और हाइजीन के अलावा शिक्षक-विद्यार्थियों के बीच बेहतर संवाद पर काम शुरू किया। संस्था से जुड़े इंटर्न आज स्कूलों में जाकर में शिक्षकों के साथ कोर्स को रोचक और आसान तरीके से पढ़ाते हैं। इसके साथ ही कुपोषित बच्चों के लिए हेल्थ कैम्प भी लगाए जाते हैं।

परिवार भी करता है सहयोग

अनूप के परिवार में मां-पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं। दोनों बच्चे आरुषि और रूशिल पढ़ रहे हैं। नौकरी छोड़ कर समाजसेवा करना सामान्य तौर पर किसी के परिवार को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उनके परिवार ने पूरा सहयोग दिया। 14 साल तक नौकरी के दौरान कमाई गई रकम का एक हिस्सा परिवार की जरूरतों के लिए इन्वेस्ट किया और बाकी से संस्था चला रहा हैं। इसके साथ ही कई कंपनियां भी आर्थिक मदद करती हैं, करीब 15 सौ लोग भी व्यक्तिगत तौर पर मदद करते हैं।

क` बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में जुटे हैं। इंस्टिट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नॉलजी से बीटेक के बाद वर्ष 2000 में स्विट्जरलैंड जाकर बस गए। ऑरेंज कम्युनिकेशन कंपनी में दस साल काम करने के बाद परिवार के साथ 2010 में लखनऊ लौट आए। इसके बाद बच्चों को एक्टिविटी बेस लर्निंग देने का काम शुरू किया, जो लगातार बढ़ता जा रहा है।

ये बच्चे अपने निवाले से मिटा रहे दूसरों की भूख

पहल से दूसरे बच्चों में भी मदद करने की भावना पैदा हो रही है। स्कूल की प्रिंसिपल की पहल पर शुरू हुए इस अभियान को अभिभावकों का भी सहयोग मिल रहा है। यही कारण है कि महज 45 दिनों में ही यह अभियान दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया।

दो महीने पहले हुई शुरुआत

जरूरतमंदों की मदद का यह सिलसिला 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के मौके पर श्रीमहाप्रभु पब्लिक स्कूल में शुरू हुआ। जब स्कूल की प्रिंसिपल रविंदर विरदी ने बच्चों से उनकी और परिवार की स्वेच्छा से जरूरतमंदों की मदद के लिए इसे शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके अभिभावक भी सहर्ष तैयार हो गए। फिर क्या था हर क्लास रूम में एक छोटी बास्केट रखी गई। जिसमें बच्चे अपने घर से लाई हुई एक्स्ट्रा रोटियां, पूड़ी या पराठे रखते और फिर क्लास मॉनिटर उसे एक बड़ी बास्केट तक पहुंचाते और फिर वह स्कूल की फूडबैंक तक पहुंचता।

प्रयागराज वह भूमि है जहां सम्राट हर्षवर्धन माघ मेले में हर वर्ष अपने वस्त्र तक दान कर देते थे। छोटी ही सही लेकिन दान की यह परंपरा यहां के एक स्कूल के बच्चे भी निभा रहे हैं। ये बच्चे अपने हिस्से के निवाले से दूसरों की भूख मिटा रहे हैं। करीब दो हजार बच्चों के टिफिन से निकलने वाली रोटियां स्कूल के पास बने अस्पताल के तीमारदारों का पेट भर रही हैं। अच्छी बात यह है कि इस

यूं करते हैं मदद

काउंसलर ऑफ द स्कूल ज्ञान प्रकाश दुबे बताते हैं कि, इस योजना को शुरू हुए 45 दिन बीत चुके हैं जिनमें से 32 दिन फूड डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है। फूड डिस्ट्रिब्यूशन सिर्फ छुट्टी के दिनों में नहीं किया जाता। इसके अलावा हर रोज बच्चे अपने टिफिन से रोटियां, पराठे या पूड़ियां देते हैं जबकि, प्रिंसिपल अचार का इंतजाम करती हैं। इस तरह मरीजों और उनके तीमारदारों को सुबह का नाश्ता मिलता है।

चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बना ठिकाना

ज्ञान प्रकाश बताते हैं कि पहले स्वरूपरानी नेहरू हॉस्पिटल में मरीजों और तीमारदारों को भोजन बांटने की योजना थी लेकिन स्कूल के पास स्थित चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में इसे शुरू किया गया। हॉस्पिटल के प्रबंधन ने इसकी सहर्ष अनुमति भी दे दी। अब यही अस्पताल स्कूल की फूडबैंक योजना का ठिकाना बन गया है। रोज स्कूल के 5 बच्चे और 2 स्टाफ फूड लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और मरीजों व तीमारदारों को बांटा जाता है। अब तो अस्पताल के लोगों को भी हमारा इंतजार रहता है।

अस्पताल में भी दिखने लगा बदलाव

योजना के को-ऑर्डिनेटर ज्ञान प्रकाश बताते हैं कि जबसे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में इसे शुरू किया गया वहां पहले से अधिक साफ-सफाई दिखने लगी है। अगर एक स्कूल की वजह से किसी हॉस्पिटल में बदलाव आ सकता है तो शहर के अन्य स्कूलों की मदद से दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है।

बच्चों में बढ़ रही दूसरों की मदद की भावना

स्कूल की प्रिंसिपल रविंदर विरदी बताती हैं कि इस योजना का एक फायदा यह हुआ कि बच्चों के स्वभाव में भी बदलाव देखा जा रहा है। बच्चों में दूसरों की मदद करने की भावना भी बढ़ी है। क्योंकि वह दूसरों की मजबूरियां और जरूरते करीब से देख पा रहे हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.

सुन्दर शाम अरोड़ा का बैंस को जवाब झूठा प्रचार करके लोगों को गुमराह ना करो

■ चंडीगढ़/नीरज

पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने आज लोक इन्साफ पार्टी (एल.आई.पी.) के प्रमुख सिमरजीत बैंस पर बरसते हुये कहा कि वह औद्योगिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड बैंक बनाने के लिए राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध झूठा प्रचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंस पर ज़ोरदार हमला बोलते हुये उद्योग मंत्री ने सरकार की तरफ से पंजाब विलेज कॉमन लैंड (रैगूलेशन) रूल्ज, 1964 में संशोधन करने के किये गये फैसले पर गलतफहमी पैदा करने के लिए उसे और लोक इन्साफ पार्टी को आड़े हाथों लिया। एल.आई.पी. द्वारा इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने की योजना को राजनैतिक स्टंट बताते हुये उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पंजाब के लोगों को बहकाना है। श्री अरोड़ा ने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए बैंस पूरी तरह झूठ और मनघड़त बातें करने में लगा हुआ हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में लोक इन्साफ पार्टी राज्य के राजनैतिक दृश्य में से पूरी तरह साफ हो गई है जिस कारण वह अपने पैर जमाने के लिए ऐसे ढंगों से हाथ -पैर मारने की कोशिश कर रही है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण लैंड बैंकों कायम करना स्वै-इच्छुक फैसला है और पंचायतों की मर्जी से जुड़ा है जिस कारण पंचायतों को कोई भी ज़मीन बेचने के लिए मज़बूर नहीं किया जायेगा। बैंस के झूठे दावों को रद्द करते हुये उन्होंने कहा कि यदि पंचायत ज़मीन बेचने के लिए सहमत है तो उसे इसका पूरा मुआवज़ा दिया जायेगा। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि यह स्कीम सिर्फ़ कुछ इलाकों तक ही सीमित है और समूचे रा%य में ऐसे 2-3 ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक ज़मीनी क्षेत्रफल नहीं है और सही ढंग से औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए यह ज़मीन काफ़ी है। उन्होंने कहा कि या तो बैंस पंजाब संबंधी बुनियादी तथ्यों से अनजान हैं या फिर अपने राजनैतिक लाभ की ख़ातिर इन तथ्यों को जानबुझ कर अनदेखा कर रहे हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास राजय का मुख्य बिंदू है और एल.आई.पी. को राज्य के विकास में कोई रूचि नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब को विकास की जरूरत है और हमारे नौजवानों को नौकरियों की परन्तु बैंस को इसकी परवाह नहीं बल्कि वह अपनी राजनैतिक नेतागीरी जमाने में लगे हुए हैं। उन्होंने झूठे दावे करके लोगों को गुमराह करने वालों से चौकस रहने के लिए कहा। श्री अरोड़ा ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए वचनबद्ध हैं और घर-घर रोज़गार के वायदे को पूरा करने को यकीनी बना रही है जिसमें औद्योगिक विकास की कारगर भूमिका है। श्री अरोड़ा ने बैंस को ऐसा झूठ प्रचार फैलाने के विरुद्ध ताड़ना करते हुये कहा कि लोग ऐसे झांसों के आने के लिए तैयार नहीं हैं।

डिप्टी कमिशनर और पुलिस कमिशनर ने नौजवानों को डॉ.बी.आर. अम्बेदकर की विचारधारा के पहरेदार बनने का किया आह्वाहन

बराबरता,सांप्रदायिक सदभावना और भ्रातृ भाव प्यार समय की जरूरत

■ जालंधर/नीरज

डिप्टी कमिशनर जालन्धर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा और पुलिस कमिशनर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने नौजवानों को आमंत्रण दिया कि भारत रत्न डा.बी.आर अंबदेकर की विचारधारा जिस में बराबरता, सांप्रदायिक सदभावना और भ्रातृ भाव प्यार वाले समाज के प्रेक्षक बनने का न्योता दिया गया। स्थानीय अंबेदकर भवन में डा.बी.आर.अंबेदकर के प्रिय-निर्वाण दिवस को समर्पित अंबेदकर सेना की तरफ से लगाए गए खूनदान कैंप का उद्घाटन करने के उपरांत डिप्टी कमिशनर और पुलिस कमिशनर जिन के साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर जसबीर सिंह भी मौजूद थे ने कहा कि डा.बी.आर.अंबेदकर की विचारधारा को जिले के हर कोने - कोने में पहुँचाने की जरूरत है जिस में नौजवान अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होने कहा कि डा.अंबेदकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए नौजवानों को उनके दिखाऐ मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता डा.बी.आर.अंबेदकर को यह सच्ची श्रद्धांजली होगी। डिप्टी कमिशनर और पुलिस कमिशनर ने कहा कि विश्व की सब से बड़े लोकतंत्र का संविधान का नक्षा तैयार करने में बाबा साहिब का योगदान विलक्षण है। दोनों आधिकारियों ने कहा कि बाबा साहिब ने अपनी सारी ज़िंदगी सामाजिक न्याय, बराबरता और दबे कुचले और गरीब लोगों के कल्याण के लिए लगा दी। उन्होने कहा कि बाबा साहिब की तरफ से कमज़ोर लोगों को मज़बूत बनाने के लिए अनेकों पहल कदमियां की जो कि पूरे विश्व में मिसाल हैं। डिप्टी कमिशनर और पुलिस कमिशनर ने कहा कि डा.बी.आर अंबेदकर पूरे विश्व में एक विलक्षण शख्सियत थे। उन्होने कहा कि भारतीय संविधान बाबा साहिब की मेहनत और दूरदृष्टी सोच के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। उन्होने नौजवानों को न्योता दिया कि जात -पात, रंग नसल और सब के लिए न्याय और बराबरता वाला समाज सृजन करने के लिए संयुक्त प्रयास किये जाएँ। इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी श्री रजिन्दर सिंह, तहसील कल्याण अधिकारी सरबजीत कौर और अन्य भी उपस्थित थे। इस से पहले संस्था के नेता राज कुमार राजू, सुखविन्दर कोटली, जस्सी तल्हण, बलविन्दर बुग्गा, जसविन्दर बल्ल, जसबीर जस्सी, तरलोक वेंडल, राम लाल, महिंद्र मेहड्डू, कीमती लाल और अन्यों की तरफ से आये सखशियतों का स्वागत किया गया।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा रूपनगर और बनूड़ में औद्योगिक जोनों के विकास के लिए मास्टर प्लान में संशोधन को हरी झंडी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

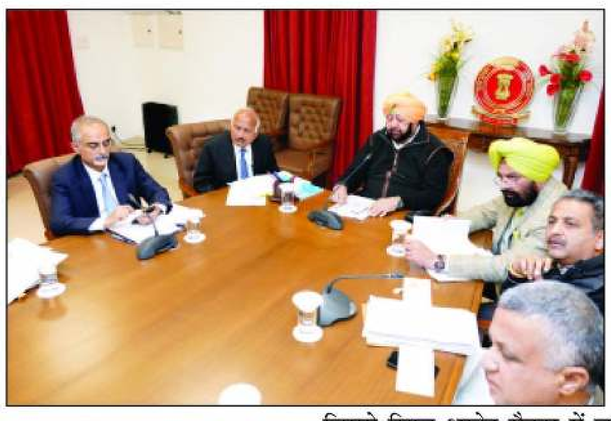

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पर केंद्रित होने के किये जा रहे प्रयासों की राह पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज रूपनगर-चण्डीगढ़ मार्ग के साथ औद्योगिक जोन के विकास के लिए रूपनगर मास्टर प्लान में संशोधन करने की मंजूरी दे दी।

पंजाब रीजनल और टाऊन प्लानिंग डिवैल्पमैंट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर इसकी 39वीं मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इस सम्बन्ध में आम लोगों के ऐतराज़ और सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ बंन माजरा, मुग़ल माजरी, भागों माजरा, चटोली, मथराड़ी, अधरेड़ा और चरहेड़ी गाँवों पर आधारित औद्योगिक जोन के विकास के लिए रास्ता साफ होगा। इससे पहले रूपनगर के नज़दीक प्रस्तावित औद्योगिक जोन संबंधी पेशकारी देते हुये टाऊन और कंट्री प्लानिंग के डायरैक्टर कविता मोहन सिंह ने बोर्ड के सदस्यों को अवगत करवाया कि इस क्षेत्र में कई औद्योगिक यूनिट पहले ही मौजूद हैं और अपने इकाईयों का विस्तार करने के लिए कुछ मसलों का सामना कर रहे हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मीटिंग में बनूड़ मास्टर प्लान में औद्योगिक जोन को मंजूरी देने भी फ़ैसला लिया गया जिससे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोहाली के नज़दीक होने के कारण इस क्षेत्र में उद्योग का सर्वपक्षीय विकास हो सकेगा। एक अन्य फैसले में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने रिहायशी जोन विकसित करने के लिए कपूरथला मास्टर प्लान में संशोधन करने के लिए हरी झंडी दे दी जो रेल कोच फैक्ट्री के सामने मौजूद सभी मौजूदा रिहायशी कलोनियों की भी व्यवस्था करेगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने हाउसिंग के प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय के प्रमुख सचिव, निवेश पंजाब के सी.ई.ओ. और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग के डायरैक्टर पर आधारित कमेटी का गठन किया है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के मौजूदा मॉडलों की जाँच करने के बाद घनत्व और एफ.ए.आर. (फ्लोर एरिया रेशियो) से सम्बन्धित मसलों को विचारेगी जिससे रियल अस्टेट सैक्टर में व्यापक विकास को यकीनी बनाया जा सके। यह कमेटी मौजूदा औद्योगिक इकाईयों के विस्तार से सम्बन्धित मुद्दों को भी जाँचेंगी और हाल ही में हुए पंजाब निवेश सम्मेलन-2019 के दौरान विभिन्न उद्योगपतियों की तरफ से माँग के मद्देनज़र उद्योग को सस्ती ज़मीन मुहैया करवाने की संभावनाएं भी तलाशेगी।मीटिंग में स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया, लोक निर्माण मंत्री विजय इंदर सिंगला, मुख्य सचिव करन अवतार सिंह, वित्त कमिश्नर राजस्व के.बी.एस. सिद्धू, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय ए.वेनू प्रसाद, प्रमुख सचिव आवास निर्माण और शहरी विकास सरवजीत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास एवं पंचायतें सीमा जैन के अलावा पटियाला विकास अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक सुरभी मलिक, गलाडा के मुख्य प्रशासक पी.एस. गिल और जालंधर विकास अथॉरिटी के मुख्य प्रशासक बख्तावर सिंह भी उपस्थित थे।

जामिया हिंसा: गिरफ्तार 10 लोगों को 31 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

दिल्ली की एक अदालत ने यहां जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समीप नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के संबंध में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों को 31 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कामरान खान ने पहले 10 गिरफ्तार लोगों में से छह लोगों मोहम्मद हनीफ, दानिश उर्फ जफर, समीर अहमद, दिलशाद, शरीफ अहमद, मोहम्मद दानिश को न्यायिक हिरासत में भेजा था।

पुलिस ने 14 दिन के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ की इजाजत मांगी थी। हालांकि, बाद में अदालत ने अन्य चार यूनुस खान, जुम्मन, अनल हसन, अनवार काला को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समीप हिंसा में शामिल होने के आरोप में सोमवार को इन्हें गिरफ्तार किया था। इनमें से कोई भी छात्र नहीं है।

नरसिंग कालेज की तरफ से जिला राहत फंड सोसाईटी में 1 लाख का योगदान

डिप्टी कमिशनर द्वारा नरसिंग कालेजों के यत्नों की प्रशंसा

■ जालंधर/नीरज

डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा को आज अलग-अलग नरसिंग कालेज की तरफ से कल्याण कार्यों के लिए सिविल सर्जन डा.गुरिन्दर कौर चावला, जिला टीकाकरण अधिकारी डा.सीमा की अगवाई में 1 लाख रुपए का चैक भेंट किया गया। डिप्टी कमिशनर ने नरसिंग कालेजों की तरफ से डाले गए इस योगदान की प्रसंशा करते कहा कि इस से जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से दिखाई गई यह दयालुता जरूरतमंद लोगों को अच्छा महसूस कराएगी। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है।

सीएम येदियुरप्पा ने किया साफ, उपचुनाव जीतने वालों को ही बनाया जाएगा मंत्री

■ बेंगलुरु/ब्यूरो

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जो हाल के उपचुनाव में विजयी हुए हैं। उपचुनाव में 15 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा विधानसभा में आसानी से बहुमत जुटाने में सफल हो गई है। इसके बाद से मंत्री पद के लिए लॉबिंग चल रही है। मंत्री पद के कई आकांक्षी अपनी पैरोकारी में मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बी श्रीरामुलू उप-मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। येदियुरप्पा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हम पहले ही कह चुके हैं कि हाल में विधानसभा उपचुनाव में जीतने वालों को ही मंत्री बनाया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि किसी अन्य को मंत्री बनाने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने कहा, ''मैं 21 या 22 दिसंबर को दिल्ली जाऊंगा और मामले (कैबिनेट विस्तार) का समाधान हो जाएगा।'' येदियुरप्पा ने कहा कि नए मंत्रियों का शपथग्रहण महीने के अंत तक हो जाएगा। कर्नाटक सरकार में 34 मंत्री हो सकते हैं जिनमें से 18 मंत्री पद भरे जा चुके हैं। विधायक जी सोमशेखर रेड्डी, मुरुगेश नीरानी, उमेश कट्टी, रमेश जारकिहोली और उप-मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवादी ने मंगलवार को येदियुरप्पा से मुलाकात की और माना जाता है कि उन्होंने कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। भाजपा सूत्रों ने कहा कि जारकिहोली ने जल संसाधन मंत्रालय के साथ खुद को उप-मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग रखी है।

डिप्टी कमिशनर ने ज़मीन की निशानदेह लिए कानूनगोआं के लिए ई.टी.एस.मशीन की प्रशिक्षण पर दिया ज़ोर

लोगों के समय और पैसे को बचाना मुख्य उद्देश्य

■ जालंधर/ब्यूरो

ज़मीन की निशानदेह की प्रक्रिया को और सुचारू बना कर लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डिप्टी कमिशनर जालन्धर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने आधिकारियों को कहा कि इलैक्ट्रॉनिकस टोटल स्टेशन मशीन की काननूगोआं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रोस्टर तैयार किया जाये।

कानूगोआं की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिशनर ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य के लोगों को ज़मीन की निशान देह में सुविधा उपलब्ध करवाने और उनके समय एवं पैसे को बचाने के लिए इलैक्ट्रॉनिकस टोटल स्टेशन मशीन को जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मशीन का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्व अधिकारियों को अधिक से अधिक शिक्षित होना चाहिए। राजस्व अधिकारियों के लिए नियमत तौर पर पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि मशीन की तीन दिनों के प्रशिक्षण से कानूनगोआं को अपना काम ओर भी सुचारू ढंग से पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।

डिप्टी कमिशनर ने अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर को कहा कि कानूनगोआं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रोस्टर बनाया जाये जिससे उनकी प्रशिक्षण शुरू की जा सकती। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अपने तजुर्बे और हुनर में और विस्तार करने के लिए इस प्रशिक्षण को ज़रूर लिया जाये। श्री शर्मा ने कहा कि यह समय की जरूरत है कि ज़मीन की निशान देही के लिए अधिकारियों को इलैक्ट्रॉनिकस टोटल स्टेशन मशीन को सुचारू ढंग से प्रयोग करने के लिए तैयार किया जाये। उन्होने यह भी कहा कि डायरैक्टर पंजाब लैंड्ड रिकार्ड की तरफ से पहले ही आधिकारियों की प्रशिक्षण का नक्षा तैयार कर लिया गया है। वर्णनयोग्य है कि इलैक्ट्रॉनिकस टोटल स्टेशन मशीन दो प्राप्त स्थानों के बीच की दूरी को पूरी दरुसती से नापने का यंत्र है। जमीन की निशान देही के लिए इस मशीन को बनाया गया है जिस के द्वारा 1 एम.एम. तक पूरी दरुसती और 5 किलोमीटर की दूरी तक बिना किसी रुकावट के मापा जा सकता है। इस अवसर पर अन्यों के इलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर जसबीर सिंह, जिला राजस्व अधिकारी जशनजीत सिंह और अन्य भी उपस्थित थे।

अतिरिक्त स्टेट इनफरमैटिक अधिकारी ने डिप्टी कमिशनर से की भेंट

ई-आफिस और आर.सी.एम.एस.सिस्टम के बारे में बताया

■ जालंधर/ब्यूरो

एन.आई.सी.पंजाब के अतिरिक्त स्टेट इनफरमैटिक अधिकारी श्री भारत भूषण शर्मा की तरफ से आज डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा से भेंट करके उनको राज्य के सरकारी कार्योलयों में उपलब्ध करवाई जा रही ई-आफिस और जिले की सभी राजस्व अदालतों में रैविन्यू कोर्ट मैनेजमेंट व्यवस्था के बारे में अवगत करवाया गया।

अतिरिक्त स्टेट इनफरमैटिक अधिकारी एन.आई.सी.पंजाब श्री भारत भूषण शर्मा की तरफ से पंजाब सरकार के सभी सरकारी कार्योलयों और राजस्व अदालतों में जल्दी शुरू किये जाने वाले इन दोनों प्रणालियों के बारे में विस्तार में बताया गया।

डिप्टी कमिशनर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने बताया कि सरकारी कार्योलयों और राजस्व अदालतों में काम को सुचारू ढंग से पूर्ण करने के लिए पहले ही ई -आफिस और रैविन्यू कोर्ट मैनेजमेंट व्यवस्था के बारे में आधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान की जा चुकी है।

उन्होने कहा कि दोनों प्रणालियों के नागरिकों के लिए वरदान सिद्ध होंगी और कोई भी नागरिक पोर्टल केस से संबन्धित विस्तारित जानकारी के इलावा केस के स्टेटस के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सकेगा और इस प्रणाली पर रजिस्ट्रेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है जबकि ई आफिस के द्वारा फाइलें आन लाईन आगे जाएंगी जिस से काम में पारदर्शिता आयेगी।

डिप्टी कमिशनर ने कहा कि जिला प्रशासन लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इन दोनों प्रणालियों को तेजी से लागू करने के लिए वचनबद्ध है। इस अवसर पर जिला इन्फर्मेशन अधिकारी ए.एस.कलसी और अन्य भी उपस्थित थे।

मिन्नी मैराथन दौड़ 6वें स्पार्क कैरियर गाईडैंस मेले को देगी मजबूत शुरूआत

■ जालंधर/नीरज

डिप्टी कमिशनर ने गुरू गोबिन्द सिंह स्टेडियम से 18 को प्रात:काल 6.30 बजे करवाई जा रही मिन्नी मैराथन के प्रबंधों का लिया जायजा

डिप्टी कमिशनर जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने जिले में करवाए जा रहे 6वें स्पार्क कैरियर गाईडैंस मेला 2019 को मज़बूत शुरुआत देने के लिए 18 दिसंबर को गुरू गोबिन्द सिंह स्टेडियम जालंधर से करवाई जा रही मिन्नी मैराथन के प्रबंधों का जायज़ा लिया गया।

जिला प्रशासकी कंपलैक्स में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिशनर ने कहा कि मिन्नी मैराथन करवाने का मुख्य उद्देश्य राज्य को सेहतमंद बनाने और नशा मुक्त करने के संदेश का प्रचार करना है। उन्होने कहा कि नौजवानों को नशे की लत से अवगत करवाना की ज़रूरत है और मिन्नी मैराथन इस में अहम भूमिका निभाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि अनुसार सही पेशे और ऊँची शिक्षा की चयन करने में सही मार्ग दर्शन प्रदान करने के अतिरिक्त स्पार्क मेला विद्यार्थियों को अच्छी स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करेगा।

श्री शर्मा ने कहा कि मिन्नी मैराथन को प्रात:काल 6.30 बजे गुरू गोबिन्द सिंह स्टेडियम से झंडी देकर रवाना किया जायेगा जो चुन्नमुन चौक, बी.एम.सी.चौक, नामदेव चौक, स्काईलार्क चौक, गुरू नानक मिशन चौक और मिल्क बार चौक से होती हुई वापिस गुरू गोबिन्द सिंह स्टेडियम पहुँच कर समाप्त होगी। उन्होने नौजवानों को न्योता दिया कि मिन्नी मैराथन दौड़ में पूरे उत्साह से पहुँच की जाये जिससे इसको सफल बनाया जा सके। उन्होने बताया कि गुरू गोबिन्द सिंह स्टेडियम जालन्धर में 19 और 20 दिसंबर को करवाए जा रहे 6वें स्पार्क कैरियर गाईडैंस मेले में जिले भर की शैक्षिक संस्थाओं से 30000 से अधिक विद्यार्थियों के पहुँचने की संभावना है।

डिप्टी कमिशनर ने कहा कि जिला प्रशासन की इस निवेकली पहल का मुख्य उद्देश्य जिले के नौजवान विद्यार्थियों को भविष्य के बारे में सही मार्ग प्रदान करके उनकी तरक्की को विश्वसनीय बनाना है।

उन्होंने कहा कि योग्य मार्ग दर्शन की कमी करके बहुत से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को दसवीं के बाद सही पेशे और पढ़ाई की चयन करने में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। उन्होने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी रुचि अनुसार सही पेशे और ऊँची पढ़ाई का चयन करने के लिए जागरूक करना है। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर जसबीर सिंह, जिला खेल अधिकारी गुरप्रीत सिंह, तैराकी प्रशिक्षक उमेश शर्मा, जिला युवक सेवाओं अधिकारी जसपाल सिंह सहोता और अन्य भी उपस्थित थे।